भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3205

उत्तर देने की तारीख : 11.03.2026

पीएम-विकास योजना

3205. श्री राजा राम सिंहः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-विकास योजना के प्रारंभ होने से लेकर आज तक इसके अंतर्गत आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके कम उपयोग, यदि कोई हों, के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पीएम-विकास के लिए बजटीय आवंटन इसी प्रकार की कारीगर और उद्यमिता योजनाओं की तुलना में मामूली रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसमें से कितने लाभार्थियों ने नौकरी हासिल की और उद्यम शुरू किया?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पूर्व में सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई रोशनी और नई मंज़िल जैसी विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू की थीं, जिन्हें अब एक व्यापक योजना 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)' के तहत एकीकृत कर दिया गया है। PM VIKAS एक 'केंद्रीय क्षेत्र की योजना' है जो कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं में उद्यमशीलता और स्कूल ड्रापआउट बच्चों को शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित है। योजना के दिशा-निर्देश जनवरी 2025 में अनुमोदित किए गए थे, जिसके बाद इस योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बजट आवंटन और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2024-25	255.43	30.00	0.00
2025-26	267.29	200.00	94.24*

*28.02.2026 तक

(ख): पीएम विकास योजना के तहत, कारीगरों को प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना और महिला नेतृत्व और उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना इस योजना के केवल दो घटक हैं, जबकि गैर-पारंपरिक रोजगार भूमिकाओं में कौशल प्रशिक्षण और स्कूल ड्रापआउट्स बच्चों के लिए शिक्षा सहायता सहित अन्य प्रमुख घटक मौजूद हैं।

(ग): इस योजना का कार्यान्वयन हाल ही में शुरू हुआ है। योजना डैशबोर्ड के अनुसार 1.50 लाख से अधिक लाभार्थियों के आवंटित लक्ष्य की तुलना में, 19,400 से अधिक अभ्यर्थियों का नामांकन किया जा चुका है, जिनमें से 790 से अधिक अभ्यर्थियों को पहले ही प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। PM VIKAS योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों में से कम से कम 75% को रोजगार दिलाना 'परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी' (PIA) का मुख्य उत्तरदायित्व है और इसे प्रशिक्षण गतिविधियों की शुरूआत के बाद प्रारंभ किया जाएगा। तथापि, योजना के तहत नामांकित और प्रशिक्षित लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	नामांकित	प्रशिक्षित
1	आंध्र प्रदेश	180	
2	असम	2315	
3	बिहार	360	
4	दिल्ली	1316	450
5	हरियाणा	283	30
6	जम्मू एवं कश्मीर	1440	
7	झारखंड	1290	
8	कर्नाटक	442	
9	केरल	117	60
10	मध्य प्रदेश	1312	76
11	महाराष्ट्र	147	
12	मेघालय	150	
13	नागालैंड	98	
14	पंजाब	4798	150
15	राजस्थान	174	
16	तमिलनाडु	60	
17	तेलंगाना	150	
18	त्रिपुरा	264	
19	उत्तर प्रदेश	3473	30
20	उत्तराखंड	1080	

	कुल	19449	796

*****